

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक: १ मई, 2011

विषय:- मै० आर०वी० आकाश गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को सोलर सी०वी० सिस्टम/सोलर पावर प्लान्ट के निर्माण हेतु, ग्राम सालियर साल्हापुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में, 10.00 एकड़ भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-986/भूमि व्यवस्था-2011, दिनांक-4 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, मै० आर०वी० आकाश गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को सोलर सी०वी० सिस्टम/सोलर पावर प्लान्ट के निर्माण हेतु, ग्राम सालियर साल्हापुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में, 10.00 एकड़ भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संसोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग/ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (सोलर सी०वी० सिस्टम/सोलर पावर प्लान्ट) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जाये।
- 5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7— क्य की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0-2005 में दिए गए नियमों/मानकों के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 8— सम्बन्धित ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9— कंपनी द्वारा उद्योग/प्लान्ट की स्थापना से पूर्व विभिन्न विभागों से वांछित अनुज्ञा, अनापत्ति/सहमति यथा—ऊर्जा विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, जिला प्रशासन तथा राज्य व केन्द्रीय कानूनों के तहत, अपेक्षित स्वीकृतियाँ स्वयं प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।
- 10— प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित ईकाई का होगा।
- 11— इकाई को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा विभाग से नियमानुसार स्वीकृति/संस्तुति प्राप्त करनी होगी।
- 12— इकाई को, भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- 13— सम्बन्धित ईकाई द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार-अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 14— किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 15— भूमि का विक्य अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्य किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 16— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार पर्यावरण तथा अन्य सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 17— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

|  
(पी०सी० शर्मा)

प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०— १८० / समदिनांकित / २०११

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मुख्य राजराज आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5— निदेशक, उद्योग विभाग औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर देहरादून।
- 6— श्री अभिषेक कौशिक, पुत्र श्री वी०बी० शर्मा, निवासी एफ-७, कृष्णा अपार्टमेन्ट, पुरुषोत्तम विहार, कन्खल, जिला हरिद्वार।
- 7— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 8— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(सन्तोष बडोनी)

अनुसचिव।